जुड़िए हमसे... पर @risingindore.news 0731-4032200

Inside page 03

राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 26 फरवरी 2025

वर्ष -12, अंक-09

मूल्य 2 रूपए, पेज- 8

आईडीए में लागू होगा गुजरात पैटर्न

प्राधिकरण अपनी योजनाओं में अब नहीं बेचेगा प्लाट

इंदौर विकास प्राधिकरण में अब गुजरात पैटर्न लागू किया जा रहा है। इस पैटर्न के तहत प्राधिकरण के द्वारा अपनी योजनाओं में प्लाट बेचने का काम नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के द्वारा अपनी योजनाओं में बड़ी जमीन तैयार कर कॉलोनाइजर को बेची जाएगी। इस जमीन पर कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी का विकास कर प्लाट बेचे जाएंगे।

राइजिंग इन्दौर
■ डॉ. जितेंद्र जाखेटिया

प्राधिकरण के कामकाज में एक बड़े बदलाव का समय आ गया है। यह बदलाव करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अनुसार अब इंदौर विकास प्राधिकरण गुजरात पैटर्न पर काम करेगा। गुजरात में सूरत और अहमदाबाद में विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरह से काम किया जाता है उसी तरह से इंदौर का विकास प्राधिकरण भी आने वाले समय में काम करता हुआ नजर आएगा। इससे प्राधिकरण के कामकाज में मूलभूत रूप से बदलाव आ जाएगा।

प्राधिकरण अभी निजी क्षेत्र और सरकारी जमीन को मिलाकर अपनी योजना घोषित करता है। इसमें निजी क्षेत्र को उसकी जमीन के बदले लैंड पूलिंग एक्ट के तहत उसकी कुल जमीन की विकसित जमीन का आधा हिस्सा दिया जाता है। बाकी बचे हुए विकसित प्लाट प्राधिकरण के द्वारा एक निश्चित कीमत निर्धारित करते हुए टेंडर के माध्यम से उससे अधिक कीमत पर आवंटित किए जाते हैं।

अब प्राधिकरण के इस कामकाज में बदलाव आ जाएगा। अब यह होगा कि प्राधिकरण एक बड़े भूभाग पर अपनी योजना घोषित कर देगा। उसके बाद में उस योजना की प्लानिंग करते हुए उस पर 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जैसे बड़े-बड़े प्लाट के हिस्से तैयार कर देगा। इनमें से हर हिस्से तक जाने के लिए 100 फीट चौड़ी सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज की लाइन डालने का कार्य प्राधिकरण कर देगा। इसके बाद प्राधिकरण के द्वारा इस तैयार किए गए हिस्से को टेंडर के माध्यम से कॉलोनाइजरों को बेचा जाएगा। कॉलोनाइजर इस हिस्से को खरीद कर उस पर अलग से अपना साइड प्लान तैयार करेगा। उस हिस्से में मौजूद जमीन पर अधो संरचना का विकास करेगा। वहां पर कॉलोनाइजर के द्वारा सड़क बनाने, ड्रेनेज की लाइन डालने, पानी की लाइन डालने, बिजली की लाइन डालने, बिजली के खंबे लगाने जैसा सारा काम किया जाएगा। इसके बाद कॉलोनाइजर के द्वारा इस जमीन पर अलग-अलग आकार के प्लाट काटे जाएंगे और यह प्लाट बेचे जाएंगे।

इस तरह से प्राधिकरण के मूल कार्यों में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। अब आने वाले समय में कॉलोनाइजर प्राधिकरण की जमीन पर प्लाट काटकर बेचते हुए नजर आएंगे। प्राधिकरण अब 600, 800, 1000, 1200 या 2400 स्क्वायर फीट के प्लाट काटने और उन्हें आवंटित करने के लिए टेंडर जारी करने जैसी सारी औपचारिकताओं से मुक्त हो जाएगा।

टीपीएस की योजनाओं में भी यही होगा

इसके साथ ही अब प्राधिकरण के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि टीपीएस की जो जो योजनाएं घोषित की गई है उन योजनाओं में भी इस प्रक्रिया को ही लागू किया जाएगा। इन योजनाओं में छोटे प्लाट का विकास करने और उन्हें बेचने के साथ-साथ सेक्टर का डेवलपमेंट करने जैसी जिम्मेदारियां से प्राधिकरण मुक्त हो जाएगा। इस स्थिति में प्राधिकरण के पास कम समय में ज्यादा काम करने की ताकत पैदा हो सकेगी। प्राधिकरण का हम्माली वाला काम समाप्त हो जाएगा।

संजय शुक्ला की पहल पर आ रहा है बदलाव

मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला की पहल पर प्राधिकरण के कामकाज में यह बदलाव आ रहा है। शुक्ला का शुरू से ही यह कहना रहा है कि प्राधिकरण को छोटे-छोटे प्लाट बनाने और बेचने जैसे कामों से मुक्त होना चाहिए। उसे शहर के विकास और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे कामों पर अपना ध्यान देना चाहिए। शुक्ला की इस चाहत को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामप्रकाश अहिरवार ने समझा। अब अहिरवार के द्वारा प्राधिकरण की नई योजनाओं में इस चाहत के अनुरूप ही बदलाव की व्यवस्था की जा रही है।

राइजिंग इंदौर अब risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

प्राधिकरण से लीज डीड से फ्री होल्ड करवाने वाले होते हैं ओटीपी के लिए परेशान

इस कार्य के लिए अलग से संपदा अधिकारी को देना चाहिए जिम्मेदारी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण से लीज डीड से फ्री होल्ड करवाने के बाद रजिस्ट्री करवाना चाहने वाले लोग ओटीपी के लिए परेशान होते हैं। इन लोगों को कई घंटे तक संपदा अधिकारी का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जनता की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य को किसी अन्य संपदा अधिकारी को सौंप दिया जाए।

प्राधिकरण से विभिन्न योजनाओं में संपत्ति प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा जब संपत्ति की पूरी राशि जमा कर दी जाती है तो प्राधिकरण उनके पक्ष में लीज डिड का संपादन करता है। प्राधिकरण में लीज डीड करवाने के बाद बहुत से लोग संपत्ति को फ्री होल्ड करवा लेते है। इसके बाद फ्री होल्ड की रजिस्ट्री चाहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा पंजीयन विभाग में संपदा 2.0 लागू कर दिया गया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्री कराने के लिए व्यक्ति को आवेदन करने के बाद रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति के पास मोबाइल पर भेजे जाने वाले ओटीपी की एंट्री करना होती है।

इस व्यवस्था के तहत प्राधिकरण से रजिस्ट्री करवाना चाहने वाले लोगों को इस ओटीपी के लिए कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। प्राधिकरण में यह ओटीपी संपदा अधिकारी मनीष श्रीवास्तव के पास आता है। मनीष श्रीवास्तव कभी साइट पर होते हैं, कभी मीटिंग में होते हैं, कभी जनता के द्वारा की जा रही शिकायत पर विभाग की स्थिति उच्च अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट करने के काम में लगे हुए होते हैं। ऐसे में वह अपने कक्ष में मौजूद नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकों को कई घंटे तक केवल ओटीपी के लिए इंतजार करना पड़ता है।

जब ओटीपी मिल जाता है तब फिर इस सिस्टम के तहत रेटिना वेरिफिकेशन होता है। इस कार्य के लिए भी फिर से संपदा अधिकारी की जरूरत होती है। सैकड़ों बार ऐसा होता है कि संपदा अधिकारी ओटीपी देने के बाद अपने कमरे से अन्य स्थान पर चले जाते हैं। फिर

ओटीपी का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद रेटिना वेरिफिकेशन के लिए उनके इंतजार का सिलसिला शुरू होता है। यह सिलसिला भी कई घंटे तक चलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब उक्त अधिकारी किसी काम से कार्यालय से बाहर चले जाते हैं लेकिन किसी को यह जानकारी ही नहीं होती है कि वह कार्यालय में नहीं है। ऐसे में रेटिना वेरिफिकेशन के लिए लोगों को अगले दिन उक्त अधिकारी के कार्यालय आने का इंतजार करना पड़ता है।

नागरिकों को हो रही इस भारी परेशानी को देखते हुए यह आवश्यक है की लीज डीड से फ्री होल्ड की रजिस्ट्री के संपादन के कार्य को प्राधिकरण में किसी अन्य अधिकारी को सौंप दिया जाए। वैसे भी प्राधिकरण में बहुत सारे संपदा अधिकारी वर्ग दो हैं। यह सभी अधिकारी पूरे दिन कार्यालय में ही मौजूद रहते हैं और लोगों से मिलते हैं। ऐसे में यदि इनमें से किसी को यह कार्य सौंप दिया जाता है तो नागरिकों का बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा बच जाएगी।

इंदौर के स्टार्टअप को मिली 30 करोड़ की फंडिंग

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर के एक स्टार्टअप को 3.3 मिलियन डॉलर (लगभग 30 करोड़ रुपए) की सीड फंडिंग मिली है। यह फंडिंग सिंगापुर की दो प्रमुख कंपनियों ने दी है। यह स्टार्टअप एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सेक्टर में काम करता है। 2022 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने अब तक 15 से ज्यादा एआई मॉडल तैयार किए हैं।

स्टार्टअप का नाम https://www.onetab.ai/ है, जिसके फाउंडर साकेत दंडोतिया, सोनल दंडोतिया और आलोक पाटील हैं। साकेत दंडोतिया वीडियो वर्स स्टार्टअप के को-फाउंडर भी हैं, जिसे तीन साल पहले लगभग 332 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग मिली थी। वीडियो वर्स स्टार्टअप एआई लर्निंग मशीन पर काम करता है। स्टार्टअप के सीनियर एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर हरीश चौहान ने बताया कि, स्टार्टअप को पिछले शनिवार 3.3 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है। इस फंडिंग का इस्तेमाल स्टार्टअप अपनी टीम को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी को अपडेट करने और विस्तार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में करेगा।

इस स्टार्टअप की शुरुआत साकेत दंडोतिया ने 2022 में 5 लोगों की टीम के साथ की थी। इसका मुख्य कार्यालय इंदौर आईटी पार्क में है और इसकी स्थापना भी यहीं हुई थी। वर्तमान में, स्टार्टअप में 15 से ज्यादा डेवलपर्स की टीम काम कर रही है।

हरीश ने स्टार्टअप की वर्किंग के बारे में बताया कि, यह ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां उपयोगकर्ता एक ही जगह पर सभी आवश्यक कार्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी वन टैब एआई वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं को टिकट मैनेजमेंट, कैंपेन संचालन, चैटिंग, एपीआई इंटीग्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं।

एक मैसेज से तैयार होती है वेबसाइट

स्टार्टअप में एआई हेड नयन हारोद ने बताया कि, आईटी सेक्टर में जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, उसे हमने ऑटो मेट कर दिया है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें- अगर आप एक किसान हैं और आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो आमतौर पर आपको इसे पूरा कराने के लिए कई डेवलपर्स से संपर्क करना पड़ेगा।

150 प्रोफेसर को कर दिया कैद

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

होलकर साइंस कॉलेज में सोमवार को छात्र नेताओं ने बड़ा हंगामा किया। उन्होंने प्रिंसिपल समेत 150 से अधिक प्रोफेसर्स को 30 मिनट तक बंधक बना लिया। सभी को हॉल में बंद कर बाहर से लकड़ी अड़ा दी, ताकि कोई बाहर न आ सके। इतना ही नहीं, उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर पूरे परिसर की बिजली भी बंद कर दी।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर में एक निजी कोचिंग द्वारा प्रायोजित होली मिलन समारोह के पोस्टर लगाए। प्रिंसिपल डॉ. अनामिका जैन ने बिना अनुमति के पोस्टर लगाए जाने की वजह से उन्हें हटवा दिया। इससे नाराज छात्र नेताओं ने प्रोफेसर्स को यशवंत हॉल में बंद कर दिया और गेट के बाहर नारेबाजी करने लगे। एक कर्मचारी किसी तरह हॉल की खिड़की से बाहर निकला और गेट खोलकर सभी को बाहर निकाला। इसके बाद प्रिंसिपल डॉ. अनामिका जैन ने कलेक्टर से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से इस आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई थी। बिना अनुमति लगे पोस्टर हटवाने पर छात्र नेताओं ने बवाल खड़ा कर दिया। इस आयोजन को किसी शर्मा कोचिंग द्वारा स्पॉन्सर किया गया था।

प्राचार्य कक्ष में भी हुआ हंगामा

कुछ दिन पहले कुछ छात्र नेता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

(एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने 7 मार्च को कॉलेज मैदान में होली सेलिब्रेशन की अनुमति मांगी थी। हालांकि, सोमवार को पूरे परिसर में शर्मा कोचिंग के सहयोग से इस आयोजन के पोस्टर लगा दिए गए थे। कॉलेज प्रशासन ने इन्हें हटवाया, तो छात्र नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। प्रिंसिपल डॉ. अनामिका जैन उस समय फैकल्टी की मीटिंग के लिए यशवंत हॉल में थीं। छात्र नेता वहां भी पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख प्रिंसिपल ने हॉल के दरवाजे अंदर से बंद करवा दिए, लेकिन गुस्साए छात्र नेताओं ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्राचार्य कक्ष में भी जमकर हंगामा किया।

छात्र नेताओं का दावा- मिली थी अनुमति

एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता रितेश पटेल ने मीडिया से कहा कि उन्होंने होली मिलन समारोह के लिए कॉलेज प्रशासन से अनुमति ली थी। अनुमति मिलने के बाद ही उन्होंने पोस्टर लगाए थे। जब प्रिंसिपल ने पोस्टर हटवा दिए और इसका कारण पूछा गया, तो वह कोई जवाब देने के बजाय सीधे मीटिंग में चली गईं। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में कलेक्टर से शिकायत कर दी है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

NHAI मध्यप्रदेश में बनाएगा 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कें

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर भोपाल हाई स्पीड कॉरिडोर के अलावा इंदौर के आउटर रिंग रोड का भी होगा निर्माण

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए की सड़क बनाई जाएगी। इसमें खास तौर पर इंदौर भोपाल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसके अलावा इंदौर में आउटर रिंग रोड का निर्माण भी किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेस वेज के निर्बाध निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति रही। इनके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. सिंह भी इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि NHAI 5 वर्षों में लगभग 60 हजार करोड़ के कार्य करेगा। प्रयास होगा कि शेष 40 हजार करोड़ के कार्य भी इन 5 वर्षों में प्रारम्भ हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण 2037 तक होना है। सिंह ने कहा कि इस MOU के कारण 2037 तक होने वाले निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में ही हो सकेगा और ऐसा करने वाला राज्य देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस एमओयू को मध्यप्रदेश के रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। एमओयू पर एनएचएआई की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. सिंह और एमपीआरडीसी की ओर से प्रबंध संचालक भरत यादव ने हस्ताक्षर किए।

यह समझौता मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के निवेश को सुनिश्चित करेगा, जिससे लगभग 4010 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। साथ ही इस एमओयू के तहत सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस समझौते के अंतर्गत हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल, 6 लेन, एक्जिस्टिंग रोड के अलावा भी विकास के और द्वार खुलेंगे।

विकास की इस श्रंखला में इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज जबलपुर नागपुर एक्सप्रेसवे, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड (पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।

यह एमओयू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025 के दौरान संपन्न हुआ, जो मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए निवेश एवं विकास की संभावनाओं को मजबूत करेगा। इस समझौते के तहत राज्य में आधुनिक सड़क परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।

कलेक्टर ने कराई निगम की प्राधिकरण से सुलह

बकाया टैक्स की वसूली में प्राधिकरण को रखें अंतिम पायदान पर

प्राधिकरण से पैसा लेने के बजाय करवा लो विकास के काम

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

बकाया टैक्स की राशि की वसूली के लिए नगर निगम के द्वारा किए जा रहे रूखे व्यवहार के कारण निगम और प्राधिकरण के बीच शुरू हुए शीत युद्ध को कलेक्टर ने सुलह करा कर समाप्त करवा दिया है। निगम को भी यह सलाह दी गई है कि प्राधिकरण से पैसा लेने के काम को प्राथमिकता में सबसे अंतिम स्थान पर रखा जाए। निगम के द्वारा प्राधिकरण को सबसे पहले स्थान पर रखकर टारगेट किया जा रहा है।

इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) दोनों ही शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियां हैं। इन दोनों के बीच लंबे समय से एक पत्र युद्ध जारी था, जिसे अब इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने समाप्त किया है। उन्होंने दोनों ही संस्थाओं के प्रमुखों को एक बैठक में अलग से समझाया और निगम का प्राधिकरण से समझौता कराया।

इंदौर नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहीं आईडीए एक समृद्ध संस्था है। निगम ने बकाया टैक्स वसूली को लेकर आईडीए को 50 करोड़ से अधिक राशि का टैक्स नोटिस भेजा था। निगम के अधिकारी आईडीए के कार्यालय भी गए और वसूली राशि को लेकर बातचीत की।

इस पर आईडीए ने भी अपनी टीम गठित की और निगम को पत्र का जवाब देते हए निगम पर ही राशि अतिरिक्त जमा होने की बात कह दी। इसके बाद दोनों के बीच कई बैठकें हुईं, लेकिन टैक्स विवाद और अधिक बढ़ गया। दोनों ही संस्थाएं एक-दूसरे पर बकाया राशि को लेकर पत्राचार करती रही।

कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्मार्ट सिटी ऑफिस में निगमायुक्त शिवम वर्मा और आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार को बुलाया। इस दौरान सिंह ने निगमायुक्त वर्मा से कहा कि वे अपनी टैक्स रिकवरी की रणनीति में आईडीए जैसी सरकारी एजेंसी को प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखें। यदि आईडीए से कुछ राशि बकाया भी है, तो वसूली करने की बजाय उस राशि का उपयोग ब्रिज, सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन विकास कार्यों के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार कर उसे आईडीए से पूर्ण कराया जाए। सूत्रों के दौरान किस दौरान चर्चा में खास तौर पर नगर निगम के अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे के द्वारा किए गए व्यवहार पर भी चर्चा हुई। इस व्यवहार पर प्राधिकरण की ओर से आपत्ति ली गई। निगम आयुक्त ने भी इस बात पर सहमति दी की निगम के अधिकारी को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्राधिकरण की ओर से यह भी बताया गया कि कोई हिसाब हो या ना हो कभी भी नगर निगम की ओर से संदेश आता है कि हमें पैसे की जरूरत है इसलिए हमें 50 करोड रुपए दे दीजिए तो हम तो किसी हिसाब के बगैर ही 50 करोड रुपए भिजवा देते हैं ताकि निगम को कामकाज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। जब निगम के प्रति प्राधिकरण का रवैया इतना बेहतर है तो फिर उसके बाद निगम को प्राधिकरण के साथ कितना घटिया व्यवहार करने में सोचना चाहिए। जब प्राधिकरण की ओर से यह तथ्य रखा गया तो उसे पर निगम की ओर से भी सहमति दी गई कि हां हम जब चाहते हैं तब प्राधिकरण हमें पैसे दे देता है इसमें कहीं कोई शक नहीं है।

कलेक्टर का मानना था कि सरकारी एजेंसियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार निगम ने कलेक्टर की बात मान ली।

इसी तरह बना था कलेक्टोरेट भवन

इंदौर में कलेक्टोरेट का नया प्रशासनिक संकुल भवन भी इसी तरह से बना था। डायवर्सन टैक्स के रूप में आईडीए पर काफी राशि बकाया थी, जिसके बदले में आईडीए ने करीब 50 करोड़ की लागत से इंदौर प्रशासन को यह भवन बनाकर दिया था। यह मॉडल सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय का एक उदाहरण है, जो न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है बल्कि शहर के विकास को भी गति देता है।

संपादकीय...

ऐसा हुआ तो अधूरा रह जाएगा प्राधिकरण का उद्देश्य...

इंदौर विकास प्राधिकरण सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में राज्य सरकार के द्वारा जब प्राधिकरण का गठन किया गया था तब उसका उद्देश्य भी निश्चित किया गया था। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि प्राधिकरण गरीब नागरिकों को मदद करेगा और उन नागरिकों के अपने घर के सपने को साकार करने का माध्यम बनेगा। यह एक अलग बात है कि प्राधिकरण अपने इस उद्देश्य से भटक गया है। प्राधिकरण एक कॉलोनाइजर के रूप में काम करने लगा है। प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं का विकास कर प्लांट बेचकर पैसे कमाने

■ गौरव गुप्ता

और उसे पैसे से शहर में विकास करने में लग गया है। इस समय प्राधिकरण में गुजरात पैटर्न लागू करने की बात की जा रही है। यदि यह पैटर्न लागू किया जाता है तो प्राधिकरण अपने उद्देश्य से बिल्कुल अलग हो जाएगा। काम और सही कीमत पर प्लांट मिलने की जनता की सारी संभावनाएं निजी क्षेत्र के हाथों में कैद हो जाएगी। यह निजी क्षेत्र मुनाफाखोरी करते हुए इतनी ऊंची कीमत पर प्लांट बचेगा कि उसे प्लाट तक आम जनता की पहुंच भी नहीं रह पाएगी। इस स्थिति में यह नया सिस्टम लागू करने से पहले एक बार फिर विचार किया जाना चाहिए।

आंतों की सफाई करने में अमृत है दालचीनी मसाले का पाउडर

डायटीशियन डॉ. आरती मेहरा ने बताया कि दालचीनी का सेवन बॉडी को डिटॉक्स करता है आंतों की सफाई करता है। जिन लोगों का पाचन खराब रहता है वो रोजाना दालचीनी का सेवन उसकी चाय बनाकर करें। दालचीनी का सेवन करने से अपच, गैस, पेट दर्द और सीने में जलन का इलाज किया जा सकता है।

बॉडी के कोने-कोने से निकल जाएंगे टॉक्सिन, बुलंद हो जाएगी गट हेल्थ

खराब पाचन पूरी सेहत को बिगाड़ देता है। पाचन को दुरुस्त करने के लिए डाइट का ध्यान रखना, लाइफस्टाइल में बदलाव करना और तनाव से दूर रहना जरूरी है। खराब पाचन न केवल पेट की समस्याएं बढ़ाता है बल्कि पूरी बॉडी पर नकारात्मक असर डालता है। पाचन तंत्र जब ठीक से काम नहीं करता तो पोषक तत्वों का सही अवशोषण नहीं हो पाता जिससे कमजोरी, थकान, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पाचन को दुरुस्त करने के लिए डाइट में हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करना जरूरी है। फाइबर रिच ये फूड पाचन सुधारने में मदद करते हैं।

पाचन को दुरुस्त करने के लिए बॉडी को हाइड्रेट करना जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। खाने को धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं और बॉडी को एक्टिव रखें। हल्की एक्सरसाइज और योगासन पाचन को दुरुस्त रखते हैं। डाइट में कुछ प्रोबायोटिक्स का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है। पाचन को दुरुस्त करने में कुछ मसालों का सेवन अमृत की तरह साबित होता है। किचन में मौजूद दालचीनी का सेवन करने से पाचन में सुधार होता है और गट हेल्थ दुरुस्त रहती है।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

मदरहुड हॉस्पिटल, डायटीशियन डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि ने बताया कि दालचीनी का सेवन बॉडी को डिटॉक्स करता है आंतों की सफाई करता है। जिन लोगों का पाचन खराब रहता है वो रोजाना दालचीनी का सेवन उसकी चाय बनाकर करें। इसका सेवन करने से अपच, गैस,पेट दर्द और सीने में जलन का इलाज करने में किया जा सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि पाचन को दुरुस्त करने में और गट हेल्थ में सुधार करने में दालचीनी का पाउडर कैसे असरदार साबित होता है।

दालचीनी से अपच, गैस और पेट दर्द का इलाज

दालचीनी का सेवन गट हेल्थ को दुरुस्त करने में दवा की तरह असर करता है। एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर दालचीनी का सेवन पेट की हेल्थ को दुरुस्त करता है। रोजाना दालचीनी का पाउडर बनाकर खाने से गट बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद मिलती है। दालचीनी हानिकारक बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाव करती है। रोजाना दालचीनी पाउडर का सेवन करने से गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और खराब बैक्टीरिया का सफाया होता है।

आंतों को हेल्दी करना चाहते हैं तो फर्मेंटिड फूड को रोज खाएं, अरबों की संख्या में बढ़ेंगे गुड बैक्टीरियां, सुधर जाएगी गट हेल्थ

दालचीनी सूजन को कंट्रोल करती है। इसमें cinnamaldehyde कंपाउंड मौजूद होता है जो आंतों की सूजन को कंट्रोल करता है। इसका सेवन करने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और लीक गट सिंड्रोम जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। रोजाना इसका सेवन करने से पाचन में सुधार होता है। दालचीनी पाचन एंजाइम की सक्रियता बढ़ाती है और पाचन को दुरुस्त करती है। दालचीनी का पाउडर चाय में डालकर या खाने में मिक्स करके खाने से एसिडिटी, अपच और ब्लोटिंग से राहत मिलती है।

दालचीनी के फायदे

दालचीनी (Cinnamon) डायबिटीज कंट्रोल करने की नेचुरल दवा है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर दालचीनी का सेवन करने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है। रोजाना दालचीनी का सेवन करने से वजन कंट्रोल होता है। दालचीनी का सेवन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है। इसका सेवन करने से भूख कंट्रोल रहती है और मोटापा कम होता है। दिल को हेल्दी रखने में दालचीनी का सेवन बेहद असरदार साबित होता है। रोजाना दालचीनी का सेवन करने से याददाश्त दुरुस्त रहती है और फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है। तनाव और एंग्जायटी को कंट्रोल करने में ये मसाला जादुई असर करता है। इसका सेवन करने से मूड में सुधार होता है।

दालचीनी के प्रयोग की विधि और मात्रा

सुबह खाली पेट पिएं दालचीनी का पानी, से सेहत को मिलेंगे जबरदस्त फायदे और शरीर की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में एक टी-स्पून या एक चुटकी से अधिक दालचीनी पाउडर का उपोयग नहीं करना चाहिए। यदि आप पाउडर के रूप की जगह दालचीनी को लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं तो एक दिन में आधा से एक इंच लंबी लकड़ी से अधिक उपयोग ना करें। क्योंकि दालचीनी की तासीर बहुत गर्म होती है। दालचीनी के सेवन से हृदय रोगों से बचाव होता है। दालचीनी खाने से सांस संबंधी रोग हावी नहीं हो पाते। कोलेस्ट्रोल की समस्या से बचने के लिए दालचीनी का सेवन किया करन चाहिए। पीरिड्स पेन की समस्या से बचने में दालचीनी बहुत लाभकारी है। शरीर को दर्द को दूर करने में दालचीनी प्रभावी भूमिका निभाती है। आप भोजन में इसका उपयोग करें। गठिया के रोगियों को दालचीनी का उपयोग दैनिक आहार में करने से लाभ होता है। दालचीनी के सेवन से बाल लंबे और घने बनते हैं। दालचीनी का नियमित उपयोग त्वचा संबंधी बीमारियों जैसे, ऐक्ने, पिंपल, एग्जिमा इत्यादि से बचाव करता है।

दालचीनी के नुकसान

भोजन में दालचीनी का अधिक उपयोग पेट में जलन की वजह बन सकता है।

दालचीनी का अधिक सेवन महिलाओं को गर्भ संबंधी समस्या दे सकता है।

गर्भवती महिलाओं के साथ ही बच्चों को स्तनपान (Breastfeeding) कराने वाली महिलाओं को भी दालचीनी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

कुछ लोगों को दालचीनी (Cinnamon) से एलर्जी (allergy) की समस्या हो सकती है. यदि ऐसा है तो आपको इसके उपयोग से बचना चाहिए।

धारा 166 के तहत दावा खारिज करने के बाद धारा 163ए MV Act के तहत दावे पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे से संबंधित अपने निर्णय दीपल गिरीशभाई सोनी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा (2004) 5 एससीसी 385 को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी बेंच को भेजा है। इस मामले में तीन जजों की बेंच ने कहा कि जहां मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजा देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, वहां दावेदार अधिनियम की धारा 163ए के तहत अपना दावा दायर नहीं कर सकते।

धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट में दावेदार को अपराधी वाहन के चालक की गलती या लापरवाही साबित करने के आधार पर मुआवजे की मांग करने की अनुमति देती है। हालांकि, धारा 163ए नो-फॉल्ट देयता की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि दावेदार को वाहन मालिक या चालक द्वारा किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 163ए एक लाभकारी कानून है। इसलिए दीपल गिरीशभाई सोनी मामले में दिए गए फैसले को स्वीकार करना मुश्किल है।

स्थिति यह है कि हम वर्तमान में दीपल गिरीशभाई सोनी (सुप्रा) में तीन जजों की पीठ के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, हमारी कठिनाई पर विचार करते हुए, जिसे हमने यहां ऊपर व्यक्त किया, पूरे सम्मान के साथ लेकिन विशुद्ध रूप से न्याय के हित में हम इस राय के हैं कि इस मामले पर एक और तीन जजों की पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए हम इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए तीन जजों की पीठ गठित करने के लिए संदर्भित करते हैं।

वर्तमान मामले में चाको जॉर्ज नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। कार को एक चालक चला रहा था और वाहन में दो नाबालिग बच्चे मौजूद थे। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिता (चाको जॉर्ज), नाबालिग बच्चों में से एक और चालक की मौत हो गई। इसके बाद मां उसके जीवित बच्चे और उसके ससुराल वालों ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की। प्रासंगिक रूप से दावा धारा 166 के तहत किया गया। न्यायाधिकरण ने याचिका यह कहते हुए खारिज की कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई। जब चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने अस्वीकृति बरकरार रखी। इस स्तर पर दावेदारों द्वारा धारा 163 ए के तहत उनके दावे पर विचार करने के लिए एक याचिका दायर की गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने दीपल गिरीशभाई सोनी के निर्णय का पालन करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। न्यायालय ने उपर्युक्त मिसाल का अवलोकन करने के बाद अधिनियम के तहत धारा 163 ए को शामिल करने पर चर्चा की।

उक्त निर्णय में अधिनियम की धारा 163 ए को सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे विभिन्न हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर नियुक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों पर लाया गया। मोटर वाहन दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती घटनाओं और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार के रूप में लापरवाही से वाहन चलाने को साबित करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण 'नो-फॉल्ट लायबिलिटी' की अधिक व्यापक योजना की आवश्यकता महसूस की गई।'' न्यायालय ने पाया कि यद्यपि इस प्रावधान निरस्त कर दिया गया, लेकिन समान प्रावधान डाला गया, यह अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह दुर्घटना होने पर लागू था। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 163ए किस प्रकार लाभकारी कानून है। इस प्रकार, वर्तमान मामले सहित, जिसमें परिवार के आधे सदस्य की मृत्यु हो गई, न्यायालय को दीपल गिरीशभाई सोनी में निर्धारित कानून की स्थिति को स्वीकार करना कठिन लगा। वास्तव में, यह निष्कर्ष कि यदि दुर्घटना किसी के अपने चालक की गलती के कारण हुई, लेकिन ऐसे मामले में भी, दावेदारों को अधिनियम की धारा 163ए के तहत आवेदन करने से प्रतिबंधित किया जाएगा; यदि उन्होंने अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन करने में असफलता पाई तो यह कानून में स्वीकार किए जाने वाला कठिन प्रस्ताव है; विशेष रूप से प्रावधान की लाभकारी प्रकृति को देखते हुए, जो अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के अन्य प्रावधानों के बावजूद भी शामिल है।''

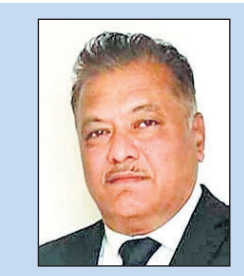

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां धारा 166 के तहत कोई दावा नहीं किया गया, न्यायाधिकरण को दावेदारों को धारा 163ए के तहत अपने दावे को बदलने का अवसर देना चाहिए, भले ही वे स्वेच्छा से ऐसा न करें। इसके अलावा, इसने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में जहां वाहन के मालिक और बीमाकर्ता दोनों को पक्ष बनाया गया था, तीसरे पक्ष के दावे के रूप में दूसरे वाहन के बीमाकर्ता पर 'नो-फॉल्ट देयता' लगाई जा सकती है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया। केसः वलसम्मा चाको और अन्य बनाम

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 क्या है?

किसी व्यक्ति को सही दावेदार माना जा सकता है और वह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मुआवजे का दावा कर सकता है यदिः वे कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि हैं जिन्हें वाहन दुर्घटना में कोई चोट लगी है। वे दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई किसी भी संपत्ति के असली मालिक हैं। वे दुर्घटना में शामिल संपत्ति के असली मालिक हैं। वे दुर्घटना के कारण मरने वाले किसी व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि हैं।

मोटर वाहन अधिनियम

मोटर वाहन अधिनियम, 166 की धारा के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने वालों को जिस वाहन ने दुर्घटना की है उसके चालक की तेजी एवं लापरवाही प्रमाणित करना होती है तभी क्षति राशि प्राप्त होगी यदि वाहन चालक की तेजी एवं लापरवाही प्रमाणित कर दी जाती है तो मृतक की इनकम और आयु के अनुसार क्षति राशि का निर्धारण होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए इस धारा के तहत, दावेदार यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता वाहन या संबंधित वाहनों के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के गलत कार्य या लापरवाही या चूक के कारण हुई थी। इसलिए, यहां नो-फॉल्ट देयता सिद्धांत लागू होता है।

मुआवजे की राशि घातक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की राशि पांच लाख रुपये होगी; स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के लिए, मुआवजे की राशि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की अनुसूची I के अनुसार 5,00,000 रुपये की प्रतिशत विकलांगता होगी]: बशर्ते कि किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता के मामले में न्यूनतम मुआवजा पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा; मामूली चोट के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं के लिए, पच्चीस हजार रुपये का एक निश्चित मुआवजा देय होगा।

GIS निवेश के साथ रहा नौकरी पर फोकस

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

भोपाल के मानव संग्रहालय में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन 22.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 13.43 लाख नौकरियों की उम्मीद बंधी है। हालांकि, ये नौकरियां निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने के बाद मिलेंगी। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इस समिट में सरकार ने निवेश के साथ नौकरी पर भी फोकस किया है। समिट के पहले दिन हुए करारों के बीच नौकरियों की उम्मीद इसलिए भी मजबूत है, क्योंकि ज्यादातर निवेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होता दिख रहा है। अवादा ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 50 हजार करोड़ के निवेश का दावा किया है। इससे 60 हजार नई नौकरियों की उम्मीद है।

उधर, रिलायंस ने भी बॉयो फ्यूल में 60 हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। इससे 60 हजार नई नौकरियों की उम्मीद है। पहले दिन गौतम अडाणी ने 1.10 लाख करोड़ के निवेश से 1.20 लाख नई नौकरियां मिलने की घोषणा की है। साथ ही ये भी कहा कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी व एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए मध्यप्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है। इसमें वे 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे।

रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर क्यों?

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े अधिकारियों ने सेक्टोरल समिट के दौरान बताया कि सरकार का फोकस ये है कि किसानों को हर हाल में दिन 10 घंटे बिजली सप्लाई हो। ताकि सिंचाई का काम बाधित न हो। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर एनर्जी से किसानों की मांग के लायक बिजली बन सके।

इसका दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि कृषि क्षेत्र पर सालाना 18 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का भार कम होगा। इमसें बिजली सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मप्र इस समय कुल बिजली उत्पादन का 15 प्रतिशत रिन्युएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है। नीमच का सोलर प्लांट 2 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बना रहा है।

ये बिजली भारतीय रेलवे को बेची जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 170 मेगावॉट बिजली परचेज करने का एग्रीमेंट किया गया है। मध्यप्रदेश अतिरिक्त बिजली उत्पादन रेलवे खरीदेगा।

ग्रीन फील्ड सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अडाणी

अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन कहा कि एमपी में ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी योजना पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश के लिए उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी योजना के बाद ग्रीन फील्ड सिटी योजना बनाई है। इसके तहत प्रथम चरण में देशभर के 8 नए शहरों का चयन होना है।

मप्र से जबलपुर- कटनी के बीच ग्रीन फील्ड सिटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस योजना के तहत 30 प्रतिशत जमीन ग्रीनरी के लिए रिजर्व होती है और उस जमीन पर सिर्फ पेड-पौधे ही लगाए जाएंगे। इन शहरों में रोड, पानी, बिजली, रेलवे लाइन, अस्पताल, स्कूल, सोलर सिस्टम और ग्रीनरी समेत अन्य सुविधाएं होंगी।

दिल्ली में शराब नीति से 2 हजार करोड़ का घाटा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। LG वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोककर रखा था। इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिस में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया।

इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी AAP ने CM हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। LG वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे, तब आप विधायकों ने मोदी-मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 AAP विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

सदन में बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि CM हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गईं। क्या PM मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं। उन्होंने कहा कि AAP सरकार के समय हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी।

दिल्ली शराब नीति पर CAG रिपोर्ट 2002 करोड़ घाटे की 4 वजह

- सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की समय पर परमिशन नहीं दी। इसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
- कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
- ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
- लोकल लाइसेंसधारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

देश को विकसित राष्ट्र बनाना है - अमित शाह

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की 130 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा है। मप्र की ये समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी। कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करे।

शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बना है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदलकर रख दिया है। अब यहां विकास के बड़े काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्ययोजना सरकार ने बनाई है, इसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अब तक सरकार के पास 30 लाख 77000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुके हैं। समिट में 5000 से अधिक बी-टू-जी और 600 से अधिक b2b कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि 1 साल के अंदर तीनों कानून पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे।

भाषण की प्रमुख बातें...

- देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बना है।
- बिजली, पानी, सड़क को लेकर जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी सरकार ने 20 साल में बदलकर रख दिया है।
- बीजेपी सरकार के 20 साल के शासन में आज यहां 5 लाख किमी रोड नेटवर्क है। 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावॉट की ऊर्जा क्षमता है। इसमें से 30 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी है।
- देशभर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा पैदा करने वाला राज्य हमारा मध्यप्रदेश है।

इस सप्ताह आपके सितारे
26 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025

किसी का रुका धन मिलेगा तो किसी का व्यय अधिक होगा

मेष- किसी व्यक्ति के सहयोग एवं अच्छे व्यवहार से मन को खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता को अल्पकष्ट संभव। संतान पक्ष पीड़ित करेगा। व्यय होगा। कारोबार ठीक-ठीक रहेगा। जीवनसाथी का शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार अच्छा रहेगा।

वृषभ- अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर इस सप्ताह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कारोबार ठीक चलेगा। आवक भी अच्छी होगी किन्तु व्यय भी अधिक होंगें। संतान पक्ष से कुछ कष्ट संभव है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगें। वाहन सुख उत्तम है। सप्ताह अच्छा है।

मिथुन- इस सप्ताह प्रेम संबंधों के मामलों में सजग रहें, अन्यथा कष्ट होगा। मानसिक तनाव ज्यादा रहेंगें। संतान पक्ष धनात्मक है। कारोबार मध्यम रहेगा। आय कम किन्तु व्यय ज्यादा होंगें। माता को कष्ट संभव है। विवादों से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें।

कर्क- इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह श्रेष्ठ है। आय भी अच्छी होगी। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगें। घर में कोई मंगल कार्य होगा। वाहन सावधानी से चलावें। भूमि का लेन-देन न करें। शेयर/ सट्टाबाजी में सतर्क रहें।

सिंह- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य अल्प न्यून रहेगा। आवक मध्यम होगी। शत्रु पीड़ित कर सकतें हैं। मित्रों का वांछित सहयोग नहीं मिलेगा। काफी समय से चली आ रही समस्या का हल संभव है। सप्ताह में 28 को सावधान रहें।

कन्या- इस सप्ताह संतान पक्ष कुछ पीड़ित कर सकता है। व्यापार-व्यवसाय अच्छा रहेगा। आय अच्छी होगी। कोई विवाद भी निपट सकता है। माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। वाहन से कष्ट संभव है। प्रेम संबंध धनात्मक रहेंगें।

तुला- इस सप्ताह किसी विवाद में पड़ सकते हैं। अतः सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग उत्तम मिलेगा। प्रेम संबंध काफी अच्छे रहेंगें। शत्रु अवश्य कष्ट दे सकते हैं। कारोबार भी अमूमन ठीक रहेगा। संतान से कष्ट संभव है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक- जीवनसाथी के स्वास्थ्य और व्यवहार की दृष्टि से यह सप्ताह अशुभ है। प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा। रुका हुआ कुछ धन प्राप्त हो सकता है। किसी का व्यवहार कष्ट देगा। कारोबार ठीक-ठीक रहेगा। वाहन सुख उत्तम है। पिता का सहयोग मिलेगा।

धनु- इस सप्ताह आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कार्य कष्ट दे सकते हैं। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कोई बहुप्रतीक्षित कार्य होगा। कारोबार की दृष्टी से सप्ताह धनात्मक है।

मकर- इस सप्ताह माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पर आंख मींच कर भरोसा न करें। संतान पक्ष कुछ परेशान कर सकता है किन्तु जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक अच्छी होगी। कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा।

कुंभ- यात्रा के योग बन सकते हैं। किन्तु उसे टालें। नौकरी अथवा व्यापार में कुछ ऋणात्मकता दिखाई देगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की तरफसे पर्याप्त सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध फले-फूलेंगे। आवक मध्यम।

मीन- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह श्रेष्ठ है। किसी रुके हुए कार्य के होने से खुशी होगी। जीवनसाथी का व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। संतान पक्ष आंशिक रूप से पीड़ित कर सकता है। बेवजह के विवादों में न पड़ें। वाहन सुख उत्तम।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ **सूर्य** - धनु राशि में ■ **चंद्र** - कर्क से कन्या राशि में ■ **मंगल** - कर्क राशि में ■ **बुध** - वृश्चिक राशि में ■ **गुरु** - वृषभ राशि में वक्री ■ **शुक्र** - मकर राशि में ■ **शनि** - कुंभ राशि में मार्गी ■ **राहु** - मीन राशि में ■ **केतु** - कन्या राशि में

मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे विकसित राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश तेज गति से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। विकास के सभी क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाएं उभरकर सामने आई हैं। प्रदेश के प्रत्येक भू-भाग में विकास और निवेश संभावनाओं को तलाशने के लिये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं से प्रवासी भारतीय परिचित हो रहे हैं। प्रदेश में सभी क्षेत्रों - आईटी, फार्मा, बॉयोटेक समेत विभिन्न सेक्टर्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 18 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब सेक्टर-वाइज समिट का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत कृषि क्षेत्र से होगी। निवेशकों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया और उद्योग-अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के प्रवासी भारतीयों और निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी क्षेत्र निवेश के लिए खुले हैं।

INVEST
MADHYA PRADESH
GLOBAL INVESTORS SUMMIT
24 & 25 FEBRUARY 2025, BHOPAL
— INFINITE POSSIBILITIES —

डॉ. यादव ने प्रवासी भारतीयों के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्त करते हुए कहा कि जब लंदन में मध्यप्रदेश के निवासी मेयर बनते हैं, तो यहां भी खुशी से आतिशबाजी की जाती हैं। जब जिम्बाब्वे में मध्यप्रदेश का रहने वाले या यहां की जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हैं, तो यहां भी खुशियां मनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक लगाव और मध्यप्रदेश की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने लोगों की सफलता पर गर्व महसूस करता है। डॉ. यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रवासी मध्यप्रदेश समिट में मध्यप्रदेश के प्रवासी नागरिकों, फ्रेंड्स ऑफ एमपी, इंडिया कनेक्ट के सदस्यों का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन में प्रदेश के प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि वे मध्यप्रदेश में निवेश कर यहां के विकास में भागीदार बनें। उन्होंने आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और प्रदेश को एक वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश सरकार करेगी पूर्ण सहयोग

प्रमुख सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग संदीप यादव ने कहा कि नीति-निर्माण से विषयों पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक, सुविध शाह ने विदेश व्यापार से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और मध्यप्रदेश में व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी दी।

बाबा महाकाल की भस्म आरती जीवन को सार्थक करने का सिखाती है सिद्धांत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल की भस्म आरती का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में पंचामृत से शरीर को निर्मल किया जाता है इसके बाद विधिवत पूजा कर अंत में भस्म से शरीर को ढंका जाता है। भस्म आरती जीवन को सार्थक करने का लघु सिद्धांत भी सिखाती है। उन्होंने महाकाल की भस्म आरती का महत्व समझाते हुए कहा कि भस्म आरती जन्म से मृत्यु तक के दर्शन का लघु रूप है। यह हर क्षण स्मरण कराती है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते जायें और समय पर हर कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि उज्जैन आध्यात्मिक नगरी के साथ ही समय (काल) की नगरी भी है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा करते हुए कहा कि यह आध्यात्मिक कुंभ है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सांसारिक और आर्थिक महाकुंभ है। मुख्यमंत्री ने महाकाल भस्म आरती के दुर्लभ दर्शन की वीआर (वर्चुअल रियलिटी) हेडसेट सेवा भी लॉन्च की। (वीआर) वीथि संकुल में उपलब्ध रहेगी।

डॉ. यादव ने समय के सदुपयोग और कर्म पर बल देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश दिया है कि सभी को अपने कर्मों के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी भारतीय सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्हें मध्यप्रदेश में निवेश करना चाहिए। इससे वे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि हजारों लोगों के जीवन में सुधार लाने का पुण्य भी अर्जित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फ्रेंड्स ऑफ एमपी (यूके चैप्टर) के आबिद फारूकी और टीम के द्वारा मध्यप्रदेश के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन प्रमोशन फ्रेम का अनावरण किया।

प्रवासी भारतीयों और उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश की प्रगति को सराहा

फ्रेंड्स ऑफ एमपी (यूएई चैप्टर) के अध्यक्ष जितेंद्र वैद्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की सशक्त और विकासपरक सोच के कारण मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हांगकांग के लीडिंग इन्वेस्टर और इंडिया कनेक्ट के ग्लोबल प्रेसिडेंट संजय नागरकर ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति की सराहना की। नागरकर ने कहा कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है और लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से यहां असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया कनेक्ट ग्रुप ने निकट भविष्य में 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश का संकल्प लिया है। हाल ही में 6 हजार 500 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू भी साइन किया गया है। उन्होंने बताया कि इंडिया कनेक्ट समूह अब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के साथ बॉयो केमिस्ट्री में एमओयू करने जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कार्य करेगा।

बंकिंघमशायर (लंदन) की मेयर सुश्री प्रेरणा भारद्वाज, फ्रेंड्स ऑफ एमपी (बॉस्टन चैप्टर) के अध्यक्ष रोहित दीक्षित, कार्यक्रम में फिजी के हाई कमिश्नर जगन्नाथ साई, जिम्बाब्वे के राज मोदी, फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के कई सदस्य और मध्यप्रदेश से जुड़े प्रवासी भारतीयों ने समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

एक बार फिर नाले से गाद निकालने का अभियान शुरू

हर साल ही नगर निगम के द्वारा बारिश का मौसम के आने के पहले नाले में से गाद निकाली जाती है। इस गाद के माध्यम से नदी के बहाव को सामान्य करने की कोशिश की जाती है ताकि बारिश के मौसम में जब बारिश का पानी गिरे तो नदी में से वह पानी आसानी के साथ बहता हुआ चल जाए। इस पानी के बहाव में कहीं कोई बाधा पैदा नहीं हो। इसी मकसद के साथ सफाई का यह अभियान चलाया जाता है। इस अभियान में हर साल नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है। निगम ने सारे शहर से गुजर रही कान्ह नदी को नाले से एक बार फिर नदी के रूप में परिवर्तित करने के काम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं लेकिन उसके बावजूद यह नदी नहीं बन सका है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

नाले को फिर नदी बनाने पर किए गए खर्चे पर श्वेत पत्र की मांग

इंदौर। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा है कि इंदौर में नाला बन चुकी कान्ह को वापस नदी बनाने पर निगम के द्वारा पिछले 10 सालों के दौरान जो खर्च किया गया है, उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। यह पवित्र कान्ह नदी थी जो की इंदौर की पहचान थी। निगम की लापरवाही और गलती ने इसे नाले के रूप में तब्दील कर दिया। अब इस नदी के नाला होने के कारण राज्य सरकार को 614 करोड रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। इसे नदी बनाने के काम पर नगर निगम 20 हजार करोड रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब और करोडों रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है।

अब तक 20 हजार करोड रु. से ज्यादा हुआ खर्च, अभी और करेंगे, निगम की लापरवाही के कारण सरकार को करना पड़ रहे है 614 करोड रुपए खर्च-चौकसे

चौकसे ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि पिछले 20 सालों से लगातार करोड़ों रुपए खर्च करते हुए नाला बन चुकी कान्ह नदी को एक बार फिर नदी के स्वरूप में लाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य पर नगर निगम ने अनाप शनाब तरीके से पैसा खर्च किया है। इस पैसे को खर्च करने के बावजूद आज तक यह नदी नहीं बन पाई है और नाला बना हुआ है। मोटे तौर पर नगर निगम 20 हजार करोड रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। इतने खर्चे के बावजूद कोई परिणाम सामने नहीं आ सका है। अभी भी नगर निगम के द्वारा इस कार्य पर और करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बनाने का काम किया जा रहा है। इस नाले पर झूठे सच्चे कामों को अंजाम देकर ही नगर निगम के द्वारा वाटर प्लस का अवार्ड हासिल किया गया।

चौकसे ने कहा कि इस नाले के कारण उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी भी नाला बन जाती है। सिंहस्थ के महापर्व में शिप्रा नदी को नदी बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को 614 करोड रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। इस राशि से राज्य सरकार के द्वारा कान्ह नाले के पानी को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए एक डक्ट बनाकर इंदौर से जा रहे इस पानी को बाईपास कर शिप्रा में मिलने से रोका जाएगा और अलग निकाल दिया जाएगा। यह स्थिति निश्चित तौर पर इंदौर के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति है।

चौकसे ने कहा कि अब यह आवश्यक है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी कर वस्तु स्थिति बताई जाए। निगम की ओर से यह जानकारी सार्वजनिक की जाए कि आखिरकार पिछले 10 सालों में इस नाले को नदी के रूप में तब्दील करने के कार्य पर कितनी राशि किस तरह से खर्च की गई है। इस समय नगर निगम के द्वारा कान्ह को नदी बनाने के काम पर कितना खर्चा और किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह खर्च और यह काम जनता के पैसे का दुरुपयोग है। बार-बार नाले को नदी बनाने का दावा करते हुए निगम के खजाने में करोड़ों रुपए का डाका डाला जा रहा है। यह आवश्यक है कि बताया जाए की आखिर जनता के पैसे में डाका डालने का यह काम किस अधिकारी के निर्देशन में कब - कब किस तरह से किया गया है।

उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा को एक पत्र लिखकर कहा है कि निगम परिषद की आगामी बैठक में निगम की ओर से यह वस्तु स्थिति पत्रक रखा जाना चाहिए। जनता को यह जानकारी दी जाना चाहिए कि नदी बनाने के कार्य को किस तरह से कितना खर्च कर किया गया और यह कार्य किस तरह से फेल हो गया। चौकसे ने कहा कि नगर निगम में पदस्थ होने वाला हर अधिकारी नाले को नदी बनाने के काम को करने के लिए एक योजना तैयार कर लेता है। इसके बाद में निगम के खजाने से इस योजना के क्रियान्वयन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण के पश्चात एक बार फिर वाटर प्लस का सर्वेक्षण होना है। इस सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम करोड़ों रुपए के खर्च के काम को शुरू करने जा रहा है। नाले की सफाई और उसे नदी बनाना हर वर्ष के भ्रष्टाचार का कीर्तिमान रचने का काम हो गया है।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- दीपक गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।